ई-संदेश

22 मई, 2025 | अंक 154

सात दिन - सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में 724 करोड़ रुपये लागत वाली 60 विकास परियोजनाओं का लोकर्पण व शिलान्यास किया

- ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता प्रदेश के सतत विकास का आधार बनेगी
- नदियों को स्वच्छ करना राज्य सरकार की प्राथमिकता
- पर्यावरण संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी
- आयुष न केवल भारत की चिकित्सकीय परम्परा का प्रतीक, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को परिभाषित करता है
- मथुरा, वृन्दावन की तर्ज पर सोरों के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा
- मंडल मुख्यालयों पर 'दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों' की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर हो
- कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता प्रदेश के सतत विकास का आधार बनेगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता प्रदेश के सतत विकास का आधार बनेगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत सभी व्यवस्थाओं को सशक्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है। राज्य सरकार इसी दिशा में मिशन मोड में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति आयोग ने ग्राम सचिवालय की अवधारणा को एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है अतः प्रदेश के सभी पंचायत भवनों को अब ग्राम सचिवालय के नाम से सम्बोधित किया जाए। यह पंचायती राज व्यवस्था को नई पहचान देने वाला परिवर्तन है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हो चुकी है, जो लोकतंत्र की अवधारणा को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम सचिवालयों में स्थापित कम्प्यूटरों के माध्यम से 'पंचायत गेटवे पोर्टल' से जुड़ी समस्त धनराशियों का भुगतान हो। इससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री जी ने राज्यस्तरीय कॉल सेंटर, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, 10-सीटर कॉल सेंटर की स्थापना, ग्राम सचिवालय की जियो फेंसिंग और इंटरनेट कॉलिंग जैसी डिजिटल पहलों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम सहायकों को 15 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए। साथ ही, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग हो। मुख्यमंत्री जी ने अमृत सरोवरों के रखरखाव, वृक्षारोपण और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में तालाबों के पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की जाए और तालाबों को 03 से 05 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाए। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सम्बन्धित गांव के विकास में किया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब आवंटन, रखरखाव और उनके उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और मत्स्य विभाग द्वारा समन्वित कार्य योजना एक निश्चित समय में तैयार की जाए। तालाब केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि ग्राम्य संस्कृति के वाहक हैं। उनकी डिसिल्टिंग समय से कर ली जाए। ग्राम सचिवालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों व प्राथमिक विद्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट विलेज की अवधारणा को प्राथमिकता दे रही है। इसके अन्तर्गत ग्राम सचिवालय, कॉमन सर्विस सेंटर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, उत्सव भवन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 कैमरे और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीणजन की 'ईज ऑफ लिविंग' में व्यापक सुधार आया है।

नदियों को स्वच्छ करना राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विगत 08 वर्षों में राज्य में 1,665 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिससे 40.72 लाख हेक्टेयर भूमि को सुरक्षा प्राप्त हुई और 319.14 लाख की आबादी लाभान्वित हुई है। प्रत्येक परियोजना गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए, ताकि मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ बचाव की दीर्घकालिक रणनीति में नदियों की ड्रेजिंग एवं चैनलाइजेशन ही सबसे प्रभावी समाधान है। वर्ष 2018 से वर्ष 2025 के बीच 60 नदियों की ड्रेजिंग परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 4.07 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिला है और 23 लाख से अधिक जनसंख्या को राहत मिली है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असि नदी के पुनर्जीवन का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। प्रदेश में मौजूद सभी रिजर्वायर की मरम्मत और डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाए और नए रिजर्वायर बनाने की योजना तैयार की जाए।

मुजफ्फरनगर में शुक्रताल तीर्थ की तर्ज पर विदुर कुटी में गंगा जी की धारा लाने की योजना पर भी तेजी से कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 08 वर्षों में प्रदेश में 1,129 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिससे 50,19,640 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा सृजित हुई है। 2,16,88,493 कृषकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

सरयू नहर, बाणसागर और अर्जुन सहायक परियोजनाएं अब पूरी हो चुकी हैं। मिशन मोड में इनके माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाए। अन्नदाता को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कोई कमी न होने पाए।

पर्यावरण संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 20 प्रतिशत तक ले जाने का हमारा लक्ष्य तभी सफल होगा, जब वृक्षारोपण जनान्दोलन का स्वरूप ले। उन्होंने आगामी 01 से 07 जुलाई के बीच वृहद पौधरोपण अभियान पूरी तैयारी, समन्वय और जनभागीदारी के साथ संचालित किए जाने के निर्देश दिए। इसके अन्तर्गत वर्ष 2025 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्षित अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सम्बन्धित विभागीय मंत्रियों को पौधरोपण अभियान की पूर्व तैयारी की गहन समीक्षा करने और अभियान की सफलता के लिए न्यूनतम 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोपे जाने वाले पौधों में अधिकतम जैव-विविधता सुनिश्चित की जाए, जिसमें फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती पौधों का संतुलित समावेश हो। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों सहित 'जीरो पॉवर्टी' की श्रेणी में चिन्हित प्रत्येक परिवार को 'सहजन' का पौधा प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में एक व्यापक 'नदी पुनरुद्धार अभियान' शुरू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य की प्रमुख नदियों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही, सभी निर्माणाधीन, प्रस्तावित तथा क्रियाशील एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर की खाली भूमि पर नियोजित वृक्षारोपण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। हर जिले की अपनी कोई न कोई विशिष्टता है, कहीं विरासत वृक्ष हैं, तो कहीं विविध प्रजातियों के वन्य जीव। इन सभी के विधिवत दस्तावेजीकरण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में 'जैव विविधता रजिस्टर' तैयार कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने सतत विकास की अवधारणा को जनमानस से जोड़ने हेतु निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 'ग्रीन चौपाल' का आयोजन किया जाए। इसके माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को अपनाने, कृषि वानिकी तथा टिकाऊ कृषि मॉडल को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हों। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक 'ग्राम-वन' की स्थापना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्माणाधीन कुकरैल नाइट सफारी की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में पायी जाने वाली कुल 6,327 गांगेय डॉल्फ़िन में से 2,397 उत्तर प्रदेश में हैं, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने इस दिशा में संरक्षण की गतिविधियों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।

आयुष न केवल भारत की चिकित्सकीय परम्परा का प्रतीक, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को परिभाषित करता है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में आयुष विभाग के कार्यों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयुष न केवल भारत की चिकित्सकीय परम्परा का प्रतीक है, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को भी परिभाषित करता है। उत्तर प्रदेश को आयुष के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में लाने के लिए सभी प्रयासों को एकजुट, योजनाबद्ध और समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक इण्टीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत आयुष की सभी पद्धतियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराया जाए। यह कदम न केवल आयुष चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य-आधारित शिक्षा प्रणाली को भी सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। सभी आयुष संस्थानों में नेचुरोपैथी और योग सेंटर की स्थापना अनिवार्य रुप से की जाए और सभी स्वीकृत शैक्षणिक व चिकित्सकीय पदों को शत-प्रतिशत भरने की कार्यवाही समयबद्ध पूरी की जाए। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रारम्भ किए जाएं, यह सेन्टर सरकारी या पी0पी0पी0 (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में संचालित हो सकते हैं।

आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध हो। प्रदेश में आयुष विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि निजी निवेशकों को आयुष सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। निजी क्षेत्र में संचालित आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, फैकल्टी एवं स्टाफ की गुणवत्ता का गहन परीक्षण कराया जाए ताकि कोई कमी न रह जाए।

आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी विशिष्ट पद्धतियां गम्भीर बीमारियों के उपचार में अत्यन्त प्रभावी हैं। इन पद्धतियों को प्रदेश के सभी आयुष संस्थानों में बढ़ावा दिया जाए। आयुष चिकित्सा की लोकप्रियता को देखते हुए यह समय भारत की परम्परागत चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत कर वैश्विक मंच पर स्थापित करने का है।

मथुरा, वृन्दावन की तर्ज पर सोरों के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनपद कासगंज में 724 करोड़ रुपये लागत की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 556 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 167 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 24 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्मिलित है। लोकार्पित परियोजनाआें में जनपद कासगंज की अत्याधुनिक रिज़र्व पुलिस लाइन्स का लोकार्पण भी शामिल है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलम्बन एवं सम्मान के लिए आगरा जोन द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड वुमेन सेफ्टी-2025 से पुरस्कृत किया। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, आवास की प्रतीकात्मक चाभी, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप आदि प्रदान किये। इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने रिज़र्व पुलिस लाइन्स कासगंज में नवनिर्मित गंगा गेस्ट हाउस, बैरकों, क्वॉटर गार्ड, जिम एवं मल्टीपरपज हॉल का निरीक्षण तथा ऑडिटोरियम का लोकार्पण/शिलालेख का अनावरण किया। उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में पौधरोपण भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूनिफॉर्म की कीमत और महत्व क्या होता है, यह आप सभी ने 'ऑपरेशन सिन्दूर' के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम के माध्यम से देखा होगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश की सेना काम कर रही है, उसी प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की भूमिका होती है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। हर दूसरे-तीसरे दिन दंगा होता था। पर्व व त्योहारों पर लोग सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश में एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। प्रदेश की पुलिस हर प्रकार के संसाधनों तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। राज्य की पुलिस माफियाओं और अपराधियों का काल बन चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज 191 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित कासगंज की अत्याधुनिक पुलिस लाइन्स का लोकार्पण भी किया जा रहा है। इस पुलिस लाइन्स में 1000 जवानों की आवासीय क्षमता से युक्त 05 बैरक बनाये गये हैं। यहां पुलिस अधिकारियों के लिए भी आवासीय सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, यहां भोजनालय, चिकित्सालय, पुलिस क्लब, लाइब्रेरी, सी0पी0सी0 कैंटीन, जलपान कैंटीन, गेस्ट हाउस, जिला नियंत्रण कक्ष, प्रशासनिक भवन, मल्टीपरपज हॉल, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, ऑडिटोरियम, पुलिस मॉडर्न स्कूल का निर्माण किया गया है।

पुलिस लाइन्स में रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने निर्धारित समय-सीमा में यह निर्माण कार्य पूर्ण किया है। यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा।

अब पुलिसकर्मी एस्बेस्टस के टूटे हुए बैरक में नहीं रहेंगे, बल्कि शानदार आवासीय सुविधाओं से युक्त हाईराइज बिल्डिंग में निवास करेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज यहां मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय का शिलान्यास भी किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर यह कम्पोजिट विद्यालय शिक्षा का मॉडल बनने जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा-06 से कक्षा-12 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी। इसके पहले चरण में जनपद स्तर, दूसरे चरण में तहसील स्तर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर तथा चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी की जाएगी। प्रदेश का प्रत्येक गरीब बच्चा आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर देश के विकास में अपना योगदान देगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन विकास, पेयजल, नगरीय विकास आदि से सम्बन्धित विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है। यहां के जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। सोरों का वही महत्व है, जो आज सम्भल का है। सम्भल भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की भूमि है और सोरों भगवान विष्णु के वराह अवतार की भूमि है। सोरों से भगवान विष्णु का तीसरा तथा सम्भल से उनका 10वां अवतार सम्बन्धित है। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे अयोध्या का विकास हुआ है तथा मथुरा-वृन्दावन के समग्र विकास की बड़ी कार्य योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही, सोरों के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रदेश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ-साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।ये निर्देश उन्होंने सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध हो। इसके लिए सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाने, शाखाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और किसानों तक ऋण की सुगमता सुनिश्चित करने पर बल दिया जाए।

उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में कोविड-19 के नवीनतम उपवेरिएंट जे0एन0-1 से सम्बन्धित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यन्त आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। फिर भी थाईलैण्ड, सिंगापुर और हाँगकाँग जैसे देशों में जे0एन0-1 उपवेरिएंट के चलते संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में भी सतत निगरानी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट मोड में रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

मंडल मुख्यालयों पर 'दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों' की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिव्यांग युवाओं के लिए संचालित शैक्षिक संस्थानों में प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के सभी बचपन डे केयर सेन्टरों, मानसिक मन्दित आश्रय केन्द्रों, समेकित विद्यालयों तथा 'ममता', 'स्पर्श' और 'संकेत' विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया जाए। यहां अध्ययनरत बच्चों से संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अभिभावकों की अपेक्षाओं को समझते हुए संस्थागत व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ की जाएं। इनके लिए लागू समस्त कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुसज्जित हों तथा लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभ प्रदान करें। विगत 08 वर्षों में विभाग के बजट में दस गुना से अधिक वृद्धि की गई है, जो दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाभार्थियों तक पूरी तत्परता से पहुँचे, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना में सांसदों और विधायकों से भी अपनी निधि से सहयोग देने का आग्रह किया जाए। दिव्यांगजनों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ स्थित 'डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय' तथा चित्रकूट स्थित 'जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय' में कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए और इन संस्थानों का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए ताकि देशभर के इच्छुक दिव्यांगजन इन संस्थानों से जुड़ सकें।उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 18 मण्डल मुख्यालयों पर 'दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों' की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाए ताकि पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से सम्बन्धित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकें।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 20 मई, 2025 को लखनऊ में डॉ० के०एन०एस० मेमोरियल हॉस्पिटल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर।

15 मई, 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

- मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि किए जाने हेतु सीड पार्क की स्थापना किए जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सीड पार्क प्रदेश स्थित कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों की उपलब्ध भूमि पर उपयुक्तता के आधार पर 150 से 200 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया जाएगा। सीड पार्क की स्थापना से प्रदेश गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। बीज प्रतिस्थापन दर (एस.आर.आर.) में सुधार से उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा कृषकों की आय बढ़ेगी। प्रदेश में उत्पादित बीजों को व्यापक बाजार प्राप्त होगा।

- मंत्री परिषद ने जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायत जिन्हें केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कम धनराशि प्राप्त हो रही है ऐसी ग्राम पंचायतों को ओ.एस.आर. (स्वयं के संसाधन से आय) अर्जित करने पर पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि राज्यांश मद में प्रदान की जाएगी।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में बारात आयोजन हेतु विवाह घर का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश की 71 विधान सभाओं में एक विवाह घर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक विवाह घर की अनुमानित लागत 1.41 करोड रुपए आकलित की गई है।

- मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश दुग्ध शाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति- 2022 (यथा संशोधित) के अनुदान/प्रोत्साहन संबंधी प्राविधानों को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अनुदान/प्रोत्साहन के समतुल्य किए जाने हेतु उक्त नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के संशोधन से उद्यमी डेरी उद्योग के अंतर्गत निवेश हेतु प्रोत्साहित होंगे। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नए रोजगार का सृजन होगा, दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध का बाजार आधारित लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा तथा उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता का प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे।

- मंत्री परिषद ने मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0 लि0 की रायबरेली इकाई के पक्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत पूर्व निर्गत एल.ओ. सी. में पी.पी.सी. (पोर्टलैंड पौजोलेना सीमेंट) उत्पाद के साथ ओ. पी. सी. (आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट) को सम्मिलित करते हुए एल. ओ.सी. में संशोधन किए जाने की संस्तुति का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। संदर्भित नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एंपावर्ड कमेटी द्वारा मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल प्रा0 लि0 के पक्ष में जारी एल.ओ.सी. में ओ.पी.सी. को सम्मिलित करते हुए संशोधन किए जाने की संस्तुति की गई और इसके अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के क्रम में मंत्री परिषद द्वारा एल.ओ.सी. में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए **निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित**